होना तथा दर बीजों के संवर्धन का अनुपात कम होना और खरीफ 1987 के दौरान अधिकांश राज्यों में सूखे की स्थिति बनी रहने के कारण रबी के लिए बीजो की अभूतपूर्व मांग का होना है। राज्य सरकार गेहूं को छोड़ कर सभी फसलों की कमी को पूरा करने के लिए खुद प्रबंध कर रही है। गेहूं के संबंध में बिहार सरकार ने भारत सरकार से गेहूं के अप्रमाणित बीजो की 3 लाख क्विंटल अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति किए जाने के प्रबंध करने का अनुरोध किया है। बिहार राज्य को गेहूं के अप्रमाणित बीजों की आपूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के जरिए भारतीय खाद्य निगम से अच्छे अनाज की खरीद के लिए एक विशेष कार्यपद्धति आरम्भ की गई है। इनके अंकुरण और रोगप्रभाव संबधी परीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् अप्रमाणित बीजों के रूप में इनकी आपूर्ति की गई। उक्त रूप में परिष्कृत इन बीजों की बगैर राज-सहायता दिए लागत 428.84 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। भारत सरकार ने बीजो पर 103.74 रुपए प्रति क्विंटल राज-सहायता देकर बिहार सरकार को ये बीज 325 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध कराए है। सम्पूर्ण कार्य बिहरा सरकार की पूर्ण संतुष्टि से रिकार्ड समय में पूरा कर लिया गया था।

जहां तक बिहार में उर्वरकों का संबध है, रबी 1987-88 के चालू मौसम में इसकी कमी होने की शिकायत प्राप्त नही हुई है। तथापि बिहार सरकार ने नवम्बर, 1987 के दौरान उर्वरकों के अतिरिक्त आबटन के लिए भारत सरकार को लिखा है तथा बिहार सरकार को उर्वरकों का यह अतिरिक्त आबंटन कर दिया गया है।

Mini Steel Plants in Andhra Pradesh

2940. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of mini steel plants functioning in Andhra Pradesh at present;

(b) how many more mini steel plants are likely to be set up by 1990 in Andhra Pradesh;

(c) whether Government have made any assessment on the functioning of mini steel plants in Andhra Pradesh; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) There are 8 licensed mini steel plants in Andhra Pradesh out of which 5 are functioning at present.

(b) Government have also granted 3 Letters of Intent for setting up new Mini Steel Plants in Andhra Pradesh. According to the schedules of implementation indicated by the entrepreneurs in their applications, it is expected that these units would be set up by 1990. In addition, one unit holding a Letter of Intent for making special steel through the Electro-Slag-refining process is also expected to go in production by 1990.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

"किसान घाट" का विकास

2941. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह के अंत्यसंस्कार स्थल "किसान घाट" के विस्तार और विकास के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है; और

(ख) इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह . (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में गिरी इमारतें

2942. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितनी इमारतें गिरी और उसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए ; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Expenditure on Imported Machineties for Asceptic Packaging Stations

2943. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how much expenditure has been incurred under Operation Flood on the import of machineries for Asceptic Packaging Stations and Paper Laminating Plants;

(b) what is the annual lease amount being paid on the machineries brought on lease from Amsterdam; and

(c) whether these machineries are being fully utilised and if not, what are the reasons for incurring such a huge expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The import content inclusive of duties and incidentals for Asceptic Packaging Stations is Rs. 3086 00 lakhs and for Paper Laminating Plants is Rs 187 00 lakhs as on 31st March, 1987.

(b) No machines have been brought on lease from Amsterdam.

(c) The progress of utilisation of the machineries is satisfactory.

Import of Dairy Products from Nuclear Affected Areas

2944. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the quantity of dairy products imported from the areas affected by nuclear accident at Chernobyl;

(b) whether it is a fact that several developing countries including Sri Lanka, Bangla Desh have rejected dairy product consignments delivered to them from the above areas and that many developed countries have banned the distribution of radioactive dairy products; and

(c) whether it is absolutely safe to use the above products, and if not, what are the reasons for distributing them for human consumption?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Gift supplies of 10,000 MT of skimmed milk powder, 2032 MT of butter oil and 2600 MT of butter was received by the erstwhile Indian Dairy Corporation (now National Dairy Development Board) from the European Economic Community during January to September, 1987.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.